

नई शिक्षा नीति के कार्यान्वयन में शैक्षणिक पुस्तकालय की प्रासंगिकता

राम कुमार अंजौरिया

ग्रंथपाल स्वामी विवेकानंद शास. महाविद्यालय सुसनेर, जिला आगर मालवा (म.प्र.)

यह लेख वर्तमान में नई शिक्षा नीति के कार्यान्वयन में शैक्षणिक पुस्तकालयों की प्रासंगिकता पर प्रकाश डालता है। इस लेख का मुख्य उद्देश्य नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप वर्तमान सूचना तकनीकी के युग में शैक्षणिक पुस्तकालयों (विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों) द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को अद्यतन करना है। महाविद्यालयों के पुस्तकालयों में अध्ययन, अध्यापन, अनुसंधान और कौशल विकास में विद्यार्थियों एवं फ़ैकल्टी को परंपरागत के साथ आधुनिक रूप में पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराना और शैक्षिक सहयोग प्रदान करना है। नई शिक्षा नीति पुस्तकालयों में पुस्तकों, पत्र-पत्रिकाओं, पुस्तकालय के प्रबंधन, पुस्तकालय स्टॉफ, पुस्तकालय फर्नीचर, पुस्तकालय में नवाचार, पुस्तकालय में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग, ई-कॉन्टेंट, डिजिटल एवं ऑनलाइन अधिगम आदि की वर्तमान में उपयोगिता पर केंद्रित है।

शब्द कुंजी : नई शिक्षा नीति 2020, शैक्षणिक पुस्तकालय, पुस्तकालयों की प्रासंगिकता।

परिचय :

भारत जैसे विशाल और विभिन्नताओं वाले देश में बढ़ती बेरोजगारी और वर्तमान परिस्थितियों में शैक्षणिक सुधार के लिए भारतीय शिक्षा नीति में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की गयी। मानव संसाधन और विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के भूतपूर्व अध्यक्ष डॉ. के. कस्तूररंगन की अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति 2020, 34 वर्ष पूर्व से जारी शिक्षा नीति 1986 के स्थान पर लागू की गई। वर्तमान में पुस्तकालयों की प्रासंगिकता को सिद्ध करने के लिए नई शिक्षा नीति के अनुरूप शैक्षणिक संस्थानों के हृदय माने जाने वाले पुस्तकालयों में परिवर्तन भी स्वाभाविक है।

नई शिक्षा नीति में पाठ्यक्रम एवं शैक्षणिक ढांचे में हुए व्यापक बदलाव के कारण उच्च शैक्षणिक संस्थानों के पुस्तकालयों को अद्यतन करने की जिम्मेदारी है। शैक्षणिक संस्थानों में पुस्तकालय की प्रासंगिकता उतनी है जितनी कि पूर्व में थी, बल्कि अब और अधिक है। उच्च शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के ज्ञान और कौशल के विकास के लिए अपने पुस्तकालयों के संसाधनों का प्रबंध करना तथा इन संसाधनों तक विद्यार्थियों को 24x7 घण्टे की पहुंच सुलभ कराना है। पुस्तकालयों का मुख्य उद्देश्य पाठकों के लिए सूचना पुनर्प्राप्ति को आसान बनाना भी है। आज वैश्विक पटल पर पुस्तकालयों में डिजिटल सूचनाओं का संग्रहण तेजी से हो रहा है। नई शिक्षा नीति के अनुसार परम्परागत पुस्तकालयों को डिजिटल लाइब्रेरी और ई-लाइब्रेरी के साथ संचालित करना भी है। इसके लिए स्थानीय एवं भारतीय भाषाओं में ई-कॉन्टेंट का निर्माण कार्य बहुत तेजी से किया जा रहा है। इंटरनेट, सूचना एवं संचार तकनीकी व सोशल मीडिया का उपयोग बहुत तेजी से होने लगा है।

उद्देश्य :-

- नई शिक्षा नीति 2020 के प्रति जागरूक करना।
- शैक्षणिक पुस्तकालयों को जानना।
- नई शिक्षा नीति के कार्यान्वयन में शैक्षणिक पुस्तकालयों की भूमिका से परिचित कराना।
- शैक्षणिक पुस्तकालयों में सूचना एवं संचार तकनीकी के बढ़ते प्रयोग एवं अन्य पुस्तकालय संसाधनों को जानना।

शोध प्रविधि :-

इस पत्र में वर्णनात्मक अध्ययन किया गया है। यह अध्ययन शैक्षणिक पुस्तकालयों का मूल्यांकन मात्र है। डाटा संग्रह हाल ही में प्रकाशित साहित्य एवं इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध जर्नल, शोध पत्र, पुस्तकों आदि से किया गया है। नई शिक्षा नीति के कार्यान्वयन और शैक्षणिक पुस्तकालयों के प्रमुख मुद्दों का विवरण प्रस्तुत करते हुए मूल्यांकन किया गया है। यह हमारी नई शिक्षा नीति के अभिन्न अंग के रूप में पुस्तकालयों के उपयोग को समझने और उसका मूल्यांकन करने का एक प्रयास है।

नई शिक्षा नीति 2020 :-

21वीं सदी की यह पहली शिक्षा नीति है। इस शिक्षा नीति का मुख्य लक्ष्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा सब तक शिक्षा की पहुंच है। सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, सांस्कृतिक संरक्षण, राष्ट्रीय एकीकरण और वैज्ञानिक उन्नति को प्राप्त करने के लिए भारी फेर बदल किए गए हैं। देश के नागरिकों को वैश्विक स्तर की उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कराना ताकि व्यक्ति, समाज और राष्ट्र का शैक्षणिक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास हो सके इसके लिए भारत जैसे विशाल देश में 2035 तक सकल नामांकन अनुपात (GER- Gross Enrolment Rate) 26.3% से बढ़ाकर 50% करने का लक्ष्य रखा गया है।

विद्यालय स्तर पर 10+2 के स्थान पर 5+3+3+4 का ढांचा तैयार करना, कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा प्रारम्भ करना, कक्षा 9 से कौशल विकास एवं इन्टर्नशिप, मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास, आनलाइन शिक्षा, बच्चे, महिला, प्रौढ़, दिव्यांग, अनुसूचित जाति-जनजाति एवं सामाजिक, आर्थिक स्तर पर पिछड़े वर्ग के सामाजिक उत्थान के लिए विशेष शिक्षा व्यवस्था के अनुरूप पुस्तकालयों को सुगम और सरल बनाने की चुनौती है।

शालेय शिक्षा जहाँ मानव व्यक्तित्व को गढ़ने का कार्य करती है, वहीं उच्च शिक्षा मानव व्यक्तित्व को तराशने का कार्य करती है। उच्च शिक्षा ही है जो व्यक्तिगत रूप से जाग्रत एवं समृद्धशाली व्यक्तित्व प्रदान करती है, साथ ही देश के नागरिकों को रोजगार, आजीविका सृजित करने और समृद्धशाली समाज एवं राष्ट्र निर्माण में सहायक होती है। इन सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को विशाल एवं बहुविषयक (विभिन्न

विषयों एवं कलाओं की शिक्षा देने वाले संस्थान) संस्थानों में परिवर्तित किया जाना है। इन संस्थानों में विद्यार्थी कला, विज्ञान, वाणिज्य आदि के भेद से परे और बिना किसी बाधा के अपनी रुचि के सभी विषयों में उच्च शिक्षा और कौशल अर्जित कर सकेंगे।



शोध विश्वविद्यालय में जहां शिक्षण के साथ साथ शोध को भी महत्व दिया गया है, वहीं शिक्षण विश्वविद्यालयों और इनसे सम्बद्ध महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर शिक्षण पर अधिक बल है। स्वायत्त महाविद्यालय ऐसे विशाल एवं बहुविधायक संस्थान होंगे जो गुणवत्तापरक स्नातक शिक्षा प्रदान करेंगे। संस्थानों का उपर्युक्त विभाजन कठोर और खण्डित न होकर, उदार एवं सतत् होगा। वर्ष 2040 तक सभी सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालय या तो स्वयं स्वायत्त बहुविधायक महाविद्यालयों में रूपांतरित हो जाएंगे या सम्बद्धता प्रदान करने वाले विश्वविद्यालयों में विलीन हो जाएंगे। इन संस्थानों में शिक्षण में उत्कृष्ट सहयोग के लिए विशाल और आधुनिक पुस्तकालय विकसित किए जाएंगे। नागरिकों को आजीवन शिक्षा से जोड़े रखने के लिए सार्वजनिक पुस्तकालय तथा कौशल विकास के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने के लिए तकनीकी पुस्तकालय भी होंगे।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और शैक्षणिक पुस्तकालयों की प्रासंगिकता :-

पुस्तकालय किसी भी शैक्षणिक संस्थान के हृदय माने जाते हैं, शैक्षणिक संस्थानों में पुस्तकालय की प्रासंगिकता उतनी है जितनी कि पूर्व में थी, बल्कि अब और अधिक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार भारत सरकार, पुस्तकालयों को सुविधा सम्पन्न और प्रासंगिक बनाने के लिए सार्थक प्रयास करेगी। पुस्तकालय में पठन सामग्री, पुस्तकालय स्टॉफ, पुस्तकालय भवन, पुस्तकालय फर्नीचर, पुस्तकालय स्वचालन, इंटरनेट सुविधा, सूचना तकनीकी, आनलाइन अधिगम आदि पुस्तकालय सुविधाओं को विकसित और अद्यतन करने का लक्ष्य है ताकि



वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार पुस्तकालयों द्वारा पाठकों को सेवाएं दी जा सकें। सभी प्रकार के पाठकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पुस्तकालयों को विकसित किया जाएगा जैसे दृष्टिहीनों के लिए ब्रेल लिपि और विभिन्न स्थानीय एवं भारतीय भाषाओं में शैक्षिक सामग्री का निर्माण किया जाएगा। पुस्तकालयों की परम्परागत सेवाओं के अतिरिक्त शैक्षणिक पुस्तकालयों को प्रासंगिक बनाने वाले प्रमुख बिन्दु निम्नलिखित हैं।

• स्थानीय एवं भारतीय भाषाओं में संग्रह –

चीन के महान दार्शनिक कनफ्यूशियस ने भाषा को लेकर कहा था कि “समाज की गलतियों या कुरीतियों को, सिर्फ समाज की भाषा को ठीक करके ही खत्म किया जा सकता है।” भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के अनुसार “निज भाषा उन्नति हवै सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिअय न हिय को सूल।” स्पष्टतः प्रभावी संचार का माध्यम भाषा ही होती है और स्थानीय भाषा में संचार ही सबसे अधिक प्रभावी होता है। अतः नई शिक्षा नीति में प्राथमिक शिक्षा स्थानीय भाषा में देने व विद्यालयीन पुस्तकालयों से लेकर उच्च शिक्षण संस्थानों एवं तकनीकी संस्थानों में स्थानीय भाषा में साहित्य तैयार करने और पुस्तकालयों में संग्रह करने का लक्ष्य है। भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में वर्णित भारतीय भाषाओं में पाठ्य सामग्री तैयार करने के साथ प्राथमिक शिक्षा के लिए अन्य स्थानीय भाषाओं में पाठ्य सामग्री तैयार की जाएगी।

• विकलांगों के लिए पुस्तकालयों की पहुंच –

नई शिक्षा नीति में समाज के सभी लोगों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए विकलांगों के लिए विशेष साहित्य सामग्री तैयार करने का लक्ष्य है। दृष्टिहीन नागरिकों के लिए ब्रेल लिपि में साहित्य सृजन व संग्रह किया जाना है। पुस्तकालयों तक विकलांगों की पहुंच को ध्यान में रखते हुए विकलांग नागरिकों के लिए विशेष सुविधाओं से युक्त पुस्तकालयों को विकसित एवं निर्मित किया जाना है।

• शैक्षणिक पुस्तकालय और शोध केंद्र –

नई शिक्षा नीति में शैक्षणिक पुस्तकालयों के लिए एक व्यापक संरचना तैयार की जाएगी। विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय पुस्तकालयों में शिक्षण एवं शोध हेतु अनुकूलित वातावरण विकसित किया जाएगा। पुस्तकालय स्वचालन, सूचना तकनीकी का अनुप्रयोग, क्लाउड बेस्ड सर्चिंग और फ्री ऑनलाइन एक्सेस के द्वारा पुस्तकालयों को आधुनिक सर्वसुविधायुक्त स्वरूप दिया जाएगा ताकि विद्यार्थी पुस्तकालयों का अधिक से अधिक उपयोग कर सकें।

• पुस्तकालय स्टाफ की सतत शिक्षा –

शैक्षणिक पुस्तकालयों के कर्मचारियों एवं अधिकारियों के द्वारा विश्व स्तर की सेवाएँ देने के लिए आवश्यक शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रावधान है। वे रिफ्रेशर और ऑरिएंटेशन प्रोग्राम के साथ अन्य आवश्यक कोर्स पूर्ण कर सकेंगे। सरकार द्वारा भी समय समय पर आवश्यक प्रशिक्षण देने की योजना बनाई गई है।

• उपयुक्त एवं पर्याप्त स्टाफ –

नई शिक्षा नीति में महाविद्यालयों, शिक्षण विश्वविद्यालयों और शोध विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों में प्रशिक्षित स्टाफ की व्यवस्था की जाएगी। विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों को फ्री ओपन एक्सेस, इंटरनेट तथा ई-रिसोर्सस की सुविधाएँ, पुस्तकालय प्रबंधन, संदर्भ सेवा आदि पुस्तकालय द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए प्रोफेशनल स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी। उच्च शिक्षा के मानकों के अनुसार पुस्तकालयों में समर्पित, उपयुक्त एवं पर्याप्त स्टाफ संरचना विकसित की जाएगी।

• सूचना तकनीकी का उपयोग –

वर्तमान में पुस्तकालयों की सूचना एवं संचार तकनीकी पर निर्भरता तेजी से बढ़ती ही जा रही है। पुस्तकालय स्वचालन, पुस्तकालय नेटवर्किंग, पुस्तकालय प्रबंधन, डिजिटल पुस्तकालय, सूचना प्रबंधन, सूचना एवं संचार तकनीकी आधारित सेवाएँ, वेब एक्सेस, इलेक्ट्रॉनिक डाक्यूमेंट डिलिवरी, सूचना स्रोत, पाठक को सूचना भेजना, ऑनलाइन निर्देश, संसाधन साझेदारी आदि के रूप में पुस्तकालयों में सूचना एवं संचार तकनीकी का प्रयोग बढ़ता ही जा रहा है। स्वाभाविक है भारतीय शैक्षणिक पुस्तकालयों को विश्व स्तर प्रदान करने के लिए नई शिक्षा नीति में सूचना एवं संचार तकनीकी का प्रयोग और तेजी से किया जाएगा।

• ऑनलाइन और आसान अधिगम –

पुस्तकालयों द्वारा वेब आधारित अधिगम के लिए नई शिक्षा नीति में सभी शैक्षणिक पुस्तकालयों को ई-ग्रंथालय, वेब पेज, क्लाउड बेस्ड एक्सेस, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस केटलॉग के माध्यम से आसानी से ऑनलाइन अधिगम कर सकेंगे। शैक्षणिक पुस्तकालयों के पाठकों को आसानी से मुक्त ऑनलाइन एक्सेस की सुविधा मिल सके और वे देश विदेश के साहित्य का ऑनलाइन अध्ययन कर सकें, इसके लिए परम्परागत शैक्षणिक पुस्तकालयों को ऑनलाइन सुविधाओं से भी जोड़ा जाएगा। ऑपन एजुकेशन रिसोर्सस जैसे – एनपीटीईएल, एकलब्य, ई-पाठशाला, ई-विद्या, ई-ज्ञानकोश, ई-ग्रिड, स्वयं, स्वयंप्रभा, यूजीसी मूक, शोधगंगा, शोधगंगोत्री, साक्षात्, ए-वियू, एनडीएल (नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी), एनएमईआईसीटी (नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इन्फोर्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलॉजी), सीईसी (कंसोर्टियम ऑफ एजुकेशनल कम्यूनिकेशन), नेशनल रिपॉजिटरी ऑफ ऑपन एजुकेशनल रिसोर्सस, नेशनल साइंस डिजिटल लाइब्रेरी आदि की सहायता से आसानी से सूचना प्राप्त कर सकेंगे।

• ई-कंटेंट निर्माण एवं संग्रह –

नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत नवीन पाठ्यक्रमानुसार ई-कंटेंट का निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है। ई-कंटेंट निर्माण हेतु उच्च शिक्षा विभाग द्वारा समितियों का गठन कर समय सीमा में पाठ्यक्रम निर्माण का कार्य पूरा करना है। पाठ्यक्रमानुसार ई-कंटेंट में पाठ्यक्रम, वीडियो लैक्चर, पावरपॉइंट प्रजेंटेशन, पीडीएफ आदि का संग्रह कर शैक्षणिक पुस्तकालयों को क्लाउड बेस्ड एक्सेस के द्वारा ऑनलाइन माध्यम से जोड़ा जाएगा।

• उपयोगी पाठ्य सामग्री एवं आकर्षक पुस्तकालय –

शैक्षणिक पुस्तकालयों में उपयोगी पाठ्य सामग्री का अधिग्रहण करने के साथ आकर्षक रंग, चित्र, पोस्टर आदि का प्रयोग किया जाएगा। ई-कॉन्टेंट भी आकर्षकरूप में तैयार किए जाएंगे। पुस्तकालयों के फर्नीचर, भवन आदि को भी आकर्षक रूप प्रदान किया जाएगा। वर्तमान में पर्यावरण के प्रति जागरूकता के लिए ग्रीन लाइब्रेरी की अवधारणा को शैक्षणिक पुस्तकालयों द्वारा अपनाया जाएगा।

• गुणवत्तापूर्ण और मानक सामग्री –

शैक्षणिक पुस्तकालयों में बौद्धिक सम्पदा अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय मानकों को ध्यान में रखते हुए पाठ्य सामग्री का अधिग्रहण किया जाएगा। पुस्तकालयों द्वारा यूजीसी मानक सूची में सुझाए गए जर्नल एवं पुस्तकों का ही अधिग्रहण किया जाएगा। पुस्तकालयों के लिए पाठ्य सामग्री का आदेश करते समय आईएसबीएन, आईएसएसएन मानकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

• संसाधन साझेदारी –

नई शिक्षा नीति के अनुसार शैक्षणिक पुस्तकालयों के संग्रह को ई-ग्रंथालय एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से जोड़ने का लक्ष्य है। सभी महाविद्यालयीन ग्रंथालय एक दूसरे के यहां उपलब्ध संग्रह को देख सकेंगे और आवश्यकता पड़ने पर संग्रह से पुस्तक, जर्नल, पत्र, पत्रिकाएँ, डिजिटल सामग्री, वीडियो लैक्चर एवं अन्य आवश्यक सामग्री को साझा कर सकेंगे।

प्रमुख सुझाव बिन्दु –

- पुस्तकालयों के लिए आधारभूत संरचना का विकास।
- शिक्षा के सार्वभौमिकरण, नामांकन में वृद्धि हेतु नवीनतम और पर्याप्त अध्ययन सामग्री।
- पुस्तकालयों में सभी प्रकार के पाठकों के लिए आसान पहुंच और उपलब्धता।
- उन्नत, नवीनतम, पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण संसाधन का संग्रह।
- पर्याप्त पुस्तकालय कर्मचारियों की उपलब्धता अनिवार्य।
- पाठकों और शिक्षकों के लिए पुस्तकालय सेवाएँ और उपयुक्त कैरियर मार्ग तैयार करना।
- पुस्तकालय एवं वाचनालय का प्रभावी संचालन।
- पुस्तकालयों का संसाधन हब के रूप में कार्य करना एवं संसाधन साझेदारी।
- विशेष नागरिकों के लिए विशेष संग्रह आदि।
- शैक्षणिक समय उपरांत और सप्ताहांत में शैक्षणिक पुस्तकालयों के परिसरों का उपयोग।
- पुस्तकालयों की स्थापना और समर्थन के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को जिम्मेदारीपूर्ण बनाना है।
- ऑनलाइन संसाधन पहुंच और डिजिटल पुस्तकालय का विकास।
- एप्स, ऑनलाइन पाठ्यक्रम, यू ट्यूब, माइल, चैनल, सोशल मीडिया, ई-संसाधन, डिजिटल संसाधन आदि की उपयोगिता सुलभ कराना

निष्कर्ष :

सूचना विस्फोट के युग और पुस्तकालयों में शैक्षिक सामग्री, पाठकों और शैक्षणिक संस्थानों की बढ़ती संख्या ने शैक्षणिक पुस्तकालयों की प्रासंगिकता पहले से और अधिक बढ़ा दी है। इंटरनेट और डिजिटल युग में पाठक का समय कैसे बचाया जा सके यह पुस्तकालयों के लिए एक चुनौती पूर्ण लक्ष्य है। नई शिक्षा नीति में पुस्तकालयों के लिए नई संरचना, पुस्तक संवर्धन, क्षेत्रीय और भारतीय संवैधानिक भाषाओं में सीखने की सामग्री, पुस्तकालयों का अधिकतम उपयोग, पाठकों का पुस्तकालयों के प्रति आकर्षण बढ़ाना, विद्यार्थियों की निर्बाध पुस्तक तक पहुंच, इंटरनेट, फ्री ऑनलाइन एक्सेस, सूचना एवं संचार तकनीक का उपयोग, सोशल मीडिया का उपयोग, संग्रह की गुणवत्ता आदि प्रमुख लक्ष्य हैं। वर्तमान में पूछताछ आधारित, खोज आधारित, चर्चा आधारित और विश्लेषण आधारित शिक्षा में पुस्तकालयाध्यक्ष की बढ़ती भूमिका और प्रोजेक्ट वर्क, शोध, डिजिटेशन वर्क एवं संदर्भ सेवा में सहयोग पुस्तकालयों की महत्ता को बढ़ाते हैं और लाइब्रेरियन को शिक्षक लाइब्रेरियन की नई भूमिका में अवतरित करते हैं।

संदर्भ–

1. https://www.education.gov.in/en/documents_reports
2. https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/statistics-new/aishe_hi.pdf
3. <https://hi.wikipedia.org/wiki>
4. <https://heerubhojwani.com/impact-of-nep-2020-on-teacher-librarian-india/>
5. <https://doi.org/10.18231/j.ijlsit.2022.004>
6. https://www.ugc.ac.in/pdfnews/5294663_Salient-Featuresofnep-Eng-merged.pdf
7. Bharti, Mukesh & Chand, Mukesh. (2022). National Education Policy-2020 and Value of the Libraries.
8. Lamani, Dr & Rathod, Dr. (2021). New Education Policy - 2020: Role of Libraries. International Journal of Research in Library Science. 7. 166. 10.26761/ijrls.7.3.2021.1436.

9^प पुरोहित, एश्वर्य : राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: एक विहंग अवलोकन, मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी. पृ. 46, 47, 48, 71,

10^प कडेल, अशोक : स्वर्णिम रचना: मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी स्वर्ण जयंती, मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल पृ.126,128